भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4629

28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

लक्षद्वीप में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं

†4629. श्री हमदुल्ला सईदः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि लक्षद्वीप के स्वास्थ्य संस्थानों में 130 नर्सिंग, पराचिकित्सा और सहायक कर्मचारियों को उनके संविदा में विस्तार नहीं मिल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त संघ राज्यक्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का आकलन किया है;

(ग) क्या प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी के कारण चिकित्सा सेवाओं में व्यवधान को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का निर्बाध चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए इन स्वास्थ्य परिचर्या कार्मिकों के संविदा का विस्तार करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार के पास लक्षद्वीप के स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में संवीदा रोजगार के कारण बार-बार आने वाली समस्या के समाधान के लिए कोई दीर्घकालिक योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं। हालाँकि, सरकार ने भारत में स्वास्थ्य परिचर्या के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान की है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव के लिए अनुमोदन प्रदान करती

है। संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप द्वारा प्रस्तुत पीआईपी प्रस्ताव के अनुसार स्वास्थ्य मानव संसाधन (एचआरएच) को कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) में अनुमोदित किया गया है और इसे निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://nhm.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=76&lid=89

संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप द्वारा सूचित किया गया है कि संविदा कर्मचारियों का सेवा-विस्तार स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की आवश्यकताओं के आधार पर उनके द्वारा किया जाने वाला एक नियमित कार्य है। 125 स्वास्थ्य परिचर्या कर्मचारियों की संविदा के विस्तार के वर्तमान मामले में, इन कार्मिकों की संविदाओं को बढ़ाने का मामला सक्रिय रूप से विचाराधीन है, और संघ राज्य क्षेत्र की स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा।

संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के प्रशासन ने सभी स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों की सटाफ संबंधी आवश्यकताओं का आकलन किया है। नियमित नर्सिंग, पैरामेडिकल और सहायक स्वास्थ्य परिचर्या कर्मचारियों के अलावा, लक्षद्वीप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत भर्ती किए गए कार्मिक भी स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं में योगदान करते हैं।

नियमित नर्सिंग, पैरामेडिकल और सहायक स्वास्थ्य परिचर्या कर्मचारियों के अलावा, लक्षद्वीप प्रशासन के पास लक्षद्वीप के सभी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में एनएचएम और राज्य संविदा के तहत नियोजित स्वास्थ्य परिचर्या कर्मी भी हैं, जिनमें नर्सिंग अधिकारी, रेडियोग्राफर, पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं। इस तैनाती का उद्देश्य चिकित्सा सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करना और प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी के कारण किसी भी संभावित व्यवधान को कम करना है।

हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया (एचडीआई) 2022-23 रिपोर्ट, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के आधार पर प्रकाशित की गई है, दिनांक 31.03.2023 तक लक्षद्वीप सहित देश में कार्यरत स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों, कमियों, उपलब्ध संसाधनों का विवरण एचडीआई 2022-23 के निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

इसके अलावा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कुछ प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं, जो इस प्रकार हैं:

नर्सिंग सेवाओं का विकास: मौजूदा नर्सिंग स्कूलों को नर्सिंग कॉलेजों में अपग्रेड करने में सहायता करने वाली इस योजना को वित्त वर्ष 2025-26 (ब.अ.) में 32.74 करोड़ रुपये का बजट आवंटन मिला है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 22 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में अब तक 19.08 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देना - मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ वहीं पर नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना: इस योजना को वित्त वर्ष 2025-26 (ब.अ.) में 200 करोड़ रुपये का बजट आवंटन मिला है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 200 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में अब तक 14 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

मानव संसाधन (एचआर) की कमी को दूर करने के लिए, एनएचएम के तहत देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डॉक्टरों और पैरामेडिक्स को चिकित्सा-प्रैक्टिस करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रकार के प्रोत्साहन और मानदेय प्रदान किए जाते हैं:

- ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा देने तथा उनके आवासीय क्वार्टरों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को हार्ड एरिया भत्ता।
- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सिजेरियन सेक्शन करने के लिए विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञों / आपातकालीन प्रसूति स्वास्थ्य परिचर्या (ईएमओसी) प्रशिक्षित डॉक्टरों, बाल रोग विशेषज्ञों और एनेस्थेटिस्ट / जीवन रक्षक एनेस्थीसिया कौशल (एलएसएएस) प्रशिक्षित डॉक्टरों को मानदेय भी प्रदान किया जाता है।
- डॉक्टरों के लिए विशेष प्रोत्साहन, समय पर एएनसी जांच और रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए एएनएम के लिए प्रोत्साहन, किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य गतिविधियों के संचालन के लिए प्रोत्साहन।
- राज्यों को विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए बातचीत से तय वेतन की पेशकश करने की भी अनुमति है, जिसमें "यू कोट वी पे" जैसी कार्यनीतियों में लचीलापन भी शामिल है।
- एनएचएम के अंतर्गत दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्राथमिकता तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार जैसे गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन भी शुरू किए गए हैं।
- विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए एनएचएम के तहत डॉक्टरों के बहु-कौशल को बढ़ावा दिया जाता है। स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए एनएचएम के तहत मौजूदा मानव संसाधन का कौशल उन्नयन एक और प्रमुख कार्यनीति है।

******